

## 27 March The Hindu

### न्यूनतम आय गारंटी योजना

- हाल ही में मुख्य विपक्षी पार्टी द्वारा यह वादा किया गया कि यदि वह सत्ता में आती है तो न्यूनतम गारंटी योजना के तहत देश के बीस प्रतिशत परिवारों को 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इस योजना के तहत न्यूनतम आय की सीमा 12 हजार रुपये मानी गई है। इस योजना को 'न्याय' नाम दिया गया है। इस योजना पर प्रतिवर्ष 3.60 लाख करोड़ का खर्च होगी। यह 2019-20 के बजटीय खर्च का 13 प्रतिशत हिस्सा होगा। एक अनुमान यह है कि इस योजना को लागू करने से सकल राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो जाएगा और इसके प्रभाव में राजकोषीय असंतुलन के साथ महंगाई में वृद्धि होगी है।

- क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम?

UBI का सिद्धांत है कि सारे मुख्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों एवं सब्सिडी योजनाओं को समाप्त कर सीधे नकद स्थानांतरित किया जाए।

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक आवधिक (Periodic), बिना शर्त नकद हस्तांतरण है। इसके लिये व्यक्ति के सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है।

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा की दो मुख्य विशेषताएँ हैं-

1. UBI अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक है।

2. यह बिना शर्त नकद ट्रांसफर है। अर्थात् किसी भी व्यक्ति को UBI हेतु पात्र होने के लिये बेरोजगारी की स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पहचान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

- UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।

- इसके लिये व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना जरूरी होगा।

- इससे पहले वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पेश की गई थी। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि अब तक की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के हस्तांतरण के मामले में निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनजर जरूरतमंदों तक सार्वभौमिक रूप से वित्तीय सहायता की सीधी पहुँच सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है, तो इससे गरीबी-उन्मूलन की प्रक्रिया तेज होगी और गरीबों के लिए बेहतर ज़िंदगी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके लिए लाभार्थियों का जनधन, आधार और मोबाइल से जुड़ा होना जरूरी होगा।

### न्यूनतम आय गारंटी योजना क्या है?

- न्यूनतम आय गारंटी योजना में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे कि श्रेणी वाले लोगों को एक निश्चित रकम प्रदान करेगी।

- यह रकम गरीबी रेखा के मानक से तय की जा सकती है। इसके तहत सरकार एक निश्चित रकम तय करती है और फिर एक मानक स्थापित कर इसका वितरण करती है।

- यह एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो केवल गरीब नागरिकों को बिना शर्त सरकार द्वारा दी जाती।

- इसके लिए व्यक्ति की आय तय मानक के अनुसार होनी चाहिए और उसे उस देश का नागरिक होना जरूरी होता है, जहाँ इसे लागू किया जाना है।

- वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कुल 950 योजनाएँ हैं और जीडीपी बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 5% है। ऐसी ज्यादातर योजनाएँ आवंटन के मामले में छोटी हैं और प्रमुख 11 योजनाओं की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50% है। इसे ध्यान में रखते हुए सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को मौजूदा स्कीमों के लाभार्थियों

के लिए विकल्प के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है।

**उद्देश्य:** आर्थिक समीक्षा में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, नागरिकों को गरिमायुक्त जीवन उपलब्ध कराना, गरीबी में कमी, रोजगार-सृजन एवं श्रम-बाजार में लोचशीलता के जरिये लोगों को कार्य-विकल्प उपलब्ध कराना, व्यापक प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय समावेशन को इस स्कीम का लक्ष्य बताया गया है और संकेतों में कहा गया है कि वर्तमान में चलाई जा रही लोक-कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में यह योजना इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहीं अधिक सहायक है।

**सैद्धांतिक आधार :** 1. सार्वभौमिकता, ताकि सभी नागरिकों को इसके दायरे में लाया जा सके;

2. बिना शर्त अर्थात् न तो आय की शर्त और न ही रोजगार की शर्त; तथा

3. बुनियादी आय, ताकि बिना किसी अतिरिक्त आय गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव हो सके।

**न्यूनतम आय गारंटी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में अंतर**

- न्यूनतम आय गारंटी विशेष श्रेणी के लोगों को दी जाने वाली न्यूनतम आय है जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना वर्षों तक दी जाने वाली न्यूनतम आय की गारंटी है।

- न्यूनतम आय गारंटी लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाने वाली सुविधा है जबकि यूबीआई उन्हें सुनिश्चित तौर पर मिलना तय है।

**UBI के पक्ष में तर्क**

- अगर भारत की बात करें तो यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और गरीबों को सब्सिडी एवं सहायता प्रदान करने वाली कई सरकारी योजनाएँ विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें GDP का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। साथ ही इनके क्रियान्वयन में भी समस्या आती है।

- वर्तमान में केंद्र सरकार की कुल 950 योजनाएँ चल रही हैं। इस योजनाओं को चलाने के लिए GDP का करीब 5 प्रतिशत खर्च होता है। ये योजनाएँ गरीबों को लाभ पहुँचा रही हैं या नहीं, यह चर्चा का विषय है।

- आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन सभी योजनाओंको यदि बंद कर दिया जाए तथा इनमें खर्च होने वाले पैसे को UBI की ओर ले जाया जाए तो गरीबों तक प्रत्यक्ष रूप से पैसा पहुँचेगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा।

- सिस्टम में अनेक खामियों के चलते जिन लोगों को वास्तव में सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी नागरिकों को बेसिक आय प्रदान कर इन समस्याओं को दूर कर सकती है।

**आगे की राह**

- सबको पैसा देने के लिये धन कहाँ से आएगा? अगर मौजूदा जन-कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ UBI को लागू करना हो, तो यह प्रश्न और भी स्वाभाविक और गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ा होता है।

- इसीलिये यह माना जाता है कि UBI तभी संभव, जब कर संरचना (Tax Structure) को प्रगतिशील या रैडिकल बनाया जाए।

- विकसित देशों में न्यूनतम मानव श्रम के उपयोग के साथ उत्पादन करने वाली मशीनों पर टैक्स लगाने का विचार चर्चित रहा है।

- भारत में भी ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है तथा उस पैसे को UBI में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- हालाँकि पूरे भारत में UBI लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी फिर भी कुछ आवश्यक कदम उठाकर इसे संभव बनाया जा सकता है।

## प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. न्यूनतम आय गारंटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-।
  1. बोल्सा फैमिलिया ब्राजील की एक स्कीम है जो 2003 में गरीब परिवारों को भत्ता देने के लिए शुरू किया गया था।
  2. वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था।
  3. यूनिवर्सल बेसिक इनकम सशर्त नकद हस्तांतरण है इसके लिए बेरोजगारी की स्थिति या सामाजिक आर्थिक पहचान को साबित करना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  - (a) 1 और 2
  - (b) 2 और 3
  - (c) केवल 3
  - (d) उपर्युक्त सभी

## मुख्य परीक्षा प्रश्न

**प्रश्न-** जनता तक प्रशासन द्वारा सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को योजनाओं के माध्यम से पहुँचाया जाता रहा है परंतु वर्तमान में असमानता, मजदूरी में धीमी वृद्धि और बढ़ते आटोमेशन के कारण यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा आर्थिक समानता के लक्ष्यों को पाने के साथ सामाजिक न्याय का भविष्य है। चर्चा कीजिए कि UBI जैसी योजनाओं का अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और ग्रामीण परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**(A Bridge to nowhere)****( आधार और नकद हस्तांतरण )**

- 2017 में एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें LPG सब्सिडी 'लाभार्थी के एयरटेल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी, और उसे इसकी जानकारी भी नहीं थी। शिकायत करने पर एयरटेल द्वारा सब्सिडी का पैसा वापस किया गया तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एयरटेल पर जुर्माना भी लगाया।
- यह मामला डायवर्टेड भुगतान से संबंधित था, जिसके अंतर्गत बैंक के भुगतान को प्राप्तकर्ता की सहमति या जानकारी के बिना गलत खाते में अंतरित किया गया। हाल के वर्षों में डायवर्टेड भुगतान एक व्यापक समस्या बन गई है। मध्यम वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन भोगी और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी श्रमिकों को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- इस डायवर्टेड भुगतान का मुख्य कारण आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) है।
- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शाखा है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का आधार नंबर उसका वित्तीय पता बन जाता है। बैंक हस्तांतरण हेतु खाता संबंधित सभी जानकारी जैसे नाम बैंक खाता संख्या और IFSC कोड प्रदान की जगह केवल अपना आधार नंबर देना होगा। APBS में बैंक खाते को शामिल करने के लिए 2 चरण अपनाए जाते हैं पहला ग्राहक के खाते को आधार नंबर से लिंक करना दूसरा NPCI द्वारा खाते की



मैपिंग करना। एक ही व्यक्ति के एक से अधिक खाते होने पर APBS द्वारा स्वाचालित रूप से सबसे नए खाते में पैसा भेजा जाता है।

- 2014 में जनधन योजना लांच की गई। इस अभियान में केंद्र सरकार द्वारा लाखों बैंक खाते खोले और उन खातों को आधार के साथ लिंक किया गया लेकिन ऐसा करते वक्त बहुत सी कमियों को ध्यान में नहीं रखा गया। इससे खातों की भ्रामक जानकारी पैदा हुई तथा आधार का उचित सत्यापन नहीं किया।

- 2014 के बाद सरकार द्वारा सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान जैसे- पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी मनरेगा मजदूरी को आधार भुगतान के अंतर्गत लाना चाहती थी। सरकार द्वारा आधार को बैंक से लिंक करने में जो सत्यापन की गलती हुई थी उसे दूर करने के लिए बैंकों द्वारा खाता धारकों को बैंकों में बुलाकर ई-केवाईसी कराई गई। जिसमें आधार नंबर और पहचान की जानकारी सत्यापित कराने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना आवश्यक था। बैंको ने ई-केवाईसी लागू करने के लिए बहुत कम समय-सीमा निर्धारित की और यह समय सीमा समाप्त होने पर लोगों के खाते बंद भी हुए।

- अनिवार्य ईकेवाईसी (e-KYC) की जानकारी न होने पर से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा, - क्योंकि आधार डेटा व बैंक डेटा के बीच कुछ विसंगतिया थी। सबसे ज्यादा पीड़ितों में वृद्धावस्था पेंशनधारी थे बहुत से लाभार्थियों को यह भी नहीं पता चला कि उनकी पेंशन क्यों बंद हो गई।

- APBS के कारण समस्या सिर्फ डायवर्टरी पेमेंट की नहीं है बल्कि बहुत से लाभार्थियों को पैसा मिल भी नहीं पाता है।

- APBS में उत्तरदायित्व की कमी है तथा अपरादर्शी भुगतान प्रणाली हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी एजेंसी उत्तरदायी नहीं हैं।

- APBS प्रणाली की परेशानियों को दूर करने के लिए एक थर्ड पार्टी निगरानी तंत्र बनाया जाए जिस NPCI द्वारा जारी मापदंडों व अन्य दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए जवाबदेह बनाए जाए।